विवरण-IV

वर्ष 1982-83 के दौरान राजस्थान के पाली जनपद में लाभान्वित समस्याग्रस्त गांवों की संख्या तथा उस पर किया गया खर्च।

कार्यक्रम	लाभान्वित समस्याग्रस्त गांवों की संख्या	व्यय (लाख रुपयों में)
1. केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम	3	24.91
2. राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	78	132.93

खाद्य संबंधी राज सहायता

176. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य की राज सहायता, जो वर्ष 1970-71 में 96 करोड़ थी, आज 1600 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार किन-किन वस्तुओं पर से राज सहायता देती है ; उसका उद्देश्य क्या है ;

(ग) क्या राज सहायता का 10 प्रतिशत लाभ समाज के ऊंचे वर्ग को मिल रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीबों के हित में लाभप्रद बनाने तथा धनी वर्ग को इस राज सहायता का लाभ न उठाने देने के लिए कदम उठायेगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) 1970-71 के दौरान भारतीय खाद्य निगम को खाद्य राज सहायता के रूप में 17.98 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की गई थी। इस प्रयोजन के लिए बजट अनुमान 1983-84 में 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

बजट अनुमान 1983-84 में खाद्य राज सहायता के रूप में किए गए 800 करोड़ रुपए (भण्डारण और मार्गस्थ हानियों के प्रावधान के बिना) के प्रावधान के मदवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :

	करोड़ रुपयों में
1. उपभोक्ता राज सहायता	1983-84
(क) गेहूं	221.00
(ख) चावल	233.00
2. खाद्यान्नों के बफर स्टाक के रख-रखाव का खर्च	309.00
3. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को खाद्यान्न पहुंचाने के लिए परिवहन राज सहायता	0.60
4. नियमित भण्डारण और मार्गस्थ हानियों के लिए तदर्थ प्रावधान	40.00
	803.60
	अथवा
पूर्णांक	800.00

खाद्य विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए भारतीय खाद्य निगम को खाद्य राज सहायता देता रहा है :—

(1) किसानों को लाभकारी मूल्य का आश्वासन देकर और उन मूल्यों पर जितनी भी मात्रा बिक्री के लिए लाई जाएगी उसको खरीदने की पेशकश करके देश में खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना ।

(2) देश भर में उचित और समान निर्गम मूल्य पर सार्वजानिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध करके और खुले बाजार के मूल्य स्थिर करने की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता के हित की रक्षा करना ।

(3) न केवल अन्तर-मौसमी स्थिरता प्रदान करने के लिए बल्कि सूखा, बाढ़ आदि के कारण फसल के न होने से उत्पन्न तात्कालिक स्थिति का सामना करने के लिए देश में खाद्य सुरक्षा के उपाय के रूप में खाद्यान्नों का पर्याप्त बफर स्टाक रखना ।

(ग) और (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जाता है, समाज के कमजोर वर्गों समेत सभी वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधाओं का लाभ उठाने वाले समाज के ऊंचे स्तर के उपभोक्ताओं की प्रतिशतता का मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं कि वे इस प्रणाली का विस्तार करें, इसे सुदृढ़ बनाएं और इसमें सुधार करें। संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रशासन की जिम्मेदारी संबधित राज्य सरकारों की होती है जोकि इस संबंध में विभिन्न कार्यविधियां निर्धारित करती हैं जिनमें उचित दर की दुकानों से जिन्स की मात्रा और इसकी देने की अवधि शामिल होती है।

Delay in Completion of Irrigation Projects

177. SHRI B.D. SINGH :
SHRIMATI JAYANTI PATNAIK :

Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) the major irrigation projects taken up by the Centre/State Governments since independence and are yet to be completed/taken up and the period by which the projects in hand were anticipated to be completed initially ;

(b) the major factors responsible for the delay in the completion/taking up of these projects ;

(c) the estimated areas likely to be irrigated with the completion of these projects ;

(d) the estimated cost escalation in respect of each of these projects by the time these are completed/taken up for execution ; and

(e) what precise measures have been taken by Government to remove the bottleneck and to accelerate the progress of their completion and to ensure that the projects under completion are commissioned according to the revised schedule and that the projects proposed to be taken up are not further delayed ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

World Bank Assistance for Irrigation Projects in Orissa

178. SHRI GIRIDHAR GOMANGO : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) the names of the major and medium irrigation projects in Orissa which are under execution by World Bank assistance and recently agreed by the World Bank to provi-